भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 346
उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2024

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

346. श्री हरीभाई पटेल:
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को किफायती और उचित कीमतों पर गैर भेदभावपूर्ण तरीके से दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के अपने प्रयास में सफल रही है, जिससे ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन को पाटा जा सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है; और
(घ) क्या गुजरात के अधिकांश ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) सरकार ने ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को किफायती और उचित कीमतों पर गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमें आरम्भ की है। वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी विभिन्न उपाय किए गए हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(i) देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। भारतनेट परियोजना के तहत बनाए गए अवसंरचना का उपयोग ब्रॉडबैंड सेवाएं जैसे वाई-फाई हॉटस्पॉट,फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) आदि प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। देश में भारतनेट परियोजना के तहत

दिनांक 30.06.2024 तक 81% ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा के लिए तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 04.08.2023 को 2,64,554 जीपी को उन्नत अवसंरचना और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दे दी है।

(ii) द्वीप समूह में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक 2,313 किलोमीटर की सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) अगस्त 2020 में चालू की गई है। मेनलैंड (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक सबमरीन ओएफसी परियोजना भी जनवरी, 2024 में चालू की गई है।

(iii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सेवा से वंचित आबादी वाले गांवों को द्वारा चरणबद्ध तरीके से मोबाइल कवरेज प्रदान किया जाता है। सरकार देश के दूरस्थ और सेवा से वंचित गांवों में सार्वभौमिक दायित्व सेवा निधि (यूएसओएफ) से टीएसपी को व्यवहार्यता अंतर निधियन के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क कवरेज प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों को लागू कर रही है।

(घ) भारतनेट परियोजना के तहत गुजरात में 14,320 ग्राम पंचायतों में से 14,316 ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। गुजरात के 18,425 गांवों में से 17,928 गांवों (97.3%) को मोबाइल सेवाओं से कवर किया गया है। इसके अलावा यूएसओएफ की 4जी सैचुरेशन परियोजना के तहत सरकार ने गुजरात सहित देश भर में सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं के सैचुरेशन की योजना बनाई है।

*****